(vii) NEED TO INCREASE WATER FLOW IN RAJASTHAN CANAL TO SAVE STANDING COTTON CROP AND TO SUPPLY PEOPLE WITH DRINKING WATER.

श्री मनफूल सिंह चौधरी (बीकानेर) : राजस्थान नहर 18000 क्यूसेक क्षमता की नहर है। लेकिन इस समय राजस्थान नहर में 2500 क्यूसेक्स पानी ही चल रहा है। इतनी बड़ी नहर में यह पानी नहीं के बराबर है। इस नहर पर बोई हुई फसलें नष्ट प्राय: हो चुकी हैं। फिर भी कुछ फसलें बची हुई हैं। उसके लिए केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप करके राजस्थान नहर में पर्याप्त पानी चलान के आदेश सम्बन्धित सरकार को दे ताकि करोड़ों रुपयों की चावल और काटन की फसल बच सके वरन् राष्ट्र में इस भारी क्षति से अन्न की कमी आयेगी। सरकार को इस बात का ध्यान होना चाहिये कि राजस्थान का यह क्षेत्र अधिकतम कपास उत्पादक क्षेत्र है और इस समय कपास और चावल की फसल खड़ी है। अत: इस क्षेत्र के किसानों और देश के हित को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार के सिंचाई मंत्री इस पर बी० बी० एम० बी० से पानी दिलाने की तुरन्त कार्यवाही करने के आदेश देने का कष्ट करें। केन्द्रीय सरकार कपास का निर्यात तक कर रही है, अत: इस सम्बन्ध में राजस्थान और पंजाब के मंत्रियों की तुरन्त मीटिंग बुला कर पानी के इस अभाव को दूर किया जाय।

राजस्थान नहर द्वारा इस क्षेत्र को जो पीने का पानी मिलता था वह गत एक मास से नहीं मिल रहा है जिससे स्थिति और भी गम्भीर हो गई है और जन-जीवन और पशु-जीवन खतरे में पड़ गया है। अत: शीघ्रातिशीघ्र राजस्थान नहर में पानी की इस कमी को पूरा किया जाय।

(viii) RELIEF MEASURES FOR THE DROUGHT-AFFECTED AREAS IN UTTAR PRADSH

श्री उमाकान्त मिश्र (मिर्जापुर) : मिर्जापुर, वाराणसी तथा सभी उत्तर प्रदेश के अन्य भागों में सूखे की भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रारम्भ में अवर्षण के कारण खरीफ की बुवाई पूरी नहीं हो सकी जो फसल बोई हुई है वह सूख गई है। बांधों में पानी की कमी के कारण फसल को बचाना कठिन हो गया है। मवेशियों के लिए चारे की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। लाखों किसानों तथा खेत मजदूरों में निराशा की भावना उत्पन्न हो गई है। सूखे का मुकाबला करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। सूखा क्षेत्र में अधिकतम घन्टे बिजली की आपूर्ति कर के नलकूप तथा लिफ्ट नहरें चलाई जाएं। लोगों को रोजगार देने के लिए राहत कार्य चलाने के निर्देश दिए जाएं तथा आगामी महीनों में पेय जल का भी संकट उत्पन्न होने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए पेय जल योजनाओं के काम में तेजी लाई जाय। सरकारी देयों की वसूली में सख्ती न बरती जाय। प्रदेश के पुराने सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सूखा समस्या के स्थायी समाधान के लिए योजना बनाई जाय। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार को उचित निर्देश तथा सहायता प्रदान करें।

(ix) ADMISSION OF RECEIPT OF A REPORT BY THE CHIEF MINISTER OF MADHYA PRADESH REGARDING MASS RAPE OF WOMEN KEPT IN POLICE CAMPS IN SHIVPURI.

SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE (Bombay North Central): The admission of receipt of a report of the mass rape of women committed in police camps in Shivpuri by